

विचार बिन्दु

अविश्वास आदमी की प्रवृत्ति को जितना बिगाड़ता है, विश्वास उतना ही बनाता है। -धर्मवीर भारती

तथाकथित सभ्य व जागरूक समाज में महिला पहलवानों के प्रति इतनी अनअपेक्षित बेरुखी क्यों?

बहुत से लोगों को 2012 में दिल्ली में निर्भया के साथ हुई विषम घटना याद होगी। दिल्ली में आम लोगों ने, मीडिया ने, विभिन्न नागरिक-युवा संगठनों ने इतने जबरदस्त गुस्से का इजहार किया कि परिणाम स्वरूप उस लड़की को बड़िया इलाज उपलब्ध करवाया गया। त्वरित गति से मुकदमा दर्ज हुआ, शीघ्रता व सावधानी पूर्वक मुकदमा जांच पूरी हुई और दोषियों को सख्त सजा मिली।

इस घटना ने, अपवादस्वरूप ही सही दिल्ली के सत्तासीनों के जमीर को भी हिला कर रख दिया। परिणाम स्वरूप जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में इस घटना के परिप्रेक्ष्य में महिला के साथ होने वाली इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लाने, इस लिए कानूनों का पुनरावलोकन भी करवाया, सुझाव मंगवाए और परिणाम स्वरूप महिलाओं के साथ अपराधिक छेड़छाड़ दुर्व्यवहार से सम्बंधित कानूनों पर नए दृष्टिकोणों से विचार व परिवर्तन शुरू हुए।

मुख्य बात यह है कि उद्देगित जनमानस के दबाव के चलते यह सब सम्भव हुआ। इस घटना के विपरीत, महिला पहलवानों के साथ हुई सेक्सुअल हैरसमेंट की घटना के जो आरोप लगाए गए उन पर विचार करें।

चूंकि इस मामले में आरोप कुरती संघ के अध्यक्ष, जो सत्ताधारी पार्टी के एक बाहुबली-धनबली सांसद है, उनके विरुद्ध लगे हैं इसलिए सबसे पहले तो खेल मंत्रालय ने, पहलवानों द्वारा ज्ञापन देने, विरोध प्रकट करने के बावजूद, इस घटना को पर्याप्त गम्भीरता व त्वरितता से नहीं लिया। परिणाम स्वरूप पहलवानों को दुबारा, संसद से 800-900 मीटर दूर पुनः धरने पर बैठना पड़ा।

फिर भी सत्ताधीशों के कानून पर जूतक नहीं रेंगी। 21 अप्रैल 23 को थाने में कम्प्लेंट दर्ज कराने पर भी दर्ज नहीं हुई तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की दखल पर ही 28 अप्रैल को दर्ज हुई। यह सम्पूर्ण सरकारी सिस्टम और हम सब लोगों के लिए लज्जाजनक है कि नागरिकों को दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े।

यह मामला तो ख्याति प्राप्त, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता महिला पहलवानों का है, जो सुप्रीम कोर्ट तक अपनी व्यथा पहुंचा सकी।

कल्पना करें जब आम आदमी के साथ ऐसी बेरुखी सिस्टम की हो (जो सामान्य बात हो चली) तो क्या वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है?

छोड़िए कि इन आरोप-प्रत्यारोपों में कौन सही कौन गलत है, छोड़िये स्तरहीन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से शिक्षित होने वाले टुट्टों को किन्तु, दुखद है कि अपवाद स्वरूप कुछ चुनिंदा पत्रकार-टीवी चैनल को छोड़ें तो कोई पत्रकार, टीवी चैनल तो आरोपी के पक्ष में पूरे मामले को जातीय, राजनीति प्रेरित, तथाकथित सन्तो के समर्थन का रंग देने में कसर नहीं छोड़ रहे, क्यों? एक अखबार की न्यूज के अनुसार तो आरोपी विभिन्न संगठनों के दबाव से पोक्सो कानून बदलवाने की बात करता है। ऐसे बयानों पर सरकार-पुलिस-सत्ताधारी दल के राजनेताओं, नागरिक संगठनों की चुप्पी अच्छा संकेत नहीं।

गनीमत है कि इस बाहुबली द्वारा 5 जून को जो जनचेतना रैली की घोषणा कर रखी थी, जिसमें संतों को भी शामिल करने की असफल प्रयास हुए, को अब निरस्त कर दिया है। एक शुभ संकेत।

अगर कुछ राजनीतिक दलों, नागरिक संगठनों के नेता, किसान-ग्रामीण संगठनों के नेता, त्वरित, निष्पक्ष जांच की आवाज उठाने, पहलवानों से मिलने जंतर-मंतर चले गए तो उसमें क्या राजनीति हुई? कोई यह तो कह नहीं रहा कि जो कुछ पहलवान कह रहे हैं, उसे ही सही मान लिया जाए।

क्या कुछ नेता, कुछ प्रतिगामी संगठन यह चाहते हैं कि इन महिला पहलवानों की व्यथा को कहीं से कोई समर्थन नहीं मिले और ऐसा क्यों, ओर क्या यह सम्पूर्ण समाज के लिए शुभ संकेत कहा जा सकता है??

सब से दुखद यह है कि सत्ताधारी दल के बड़े नेता-पदाधिकारी खुल कर यह मांग भी नहीं कर पा रहे कि इस मामले में जल्दी से जल्दी न्यायपूर्ण जांच हो।

क्या पोक्सो एक्ट के दूसरे आरोपियों को इतनी छूट मिलते पडा-सुना ?? नीचता और घृष्टता की बानगी देखिए- किस-किस प्रकार के प्रश्न उछाले जा रहे हैं--मामला इतने दिनों बाद कैसे रिपोर्ट किया? पहलवानों के पास क्या प्रमाण है बताए, जैसे कि जांच अधिकारी वे ही हैं?

कोई वीडियो या ऑरल रिकार्डिंग हो तो बताएं? क्या कहा जाए इन बुद्धिहीनों के सवाल पर? यह बात तो उनके तभी समझ आए जब, दुर्भाग्यवश और ईश्वर न करे ऐसा हो किन्तु उनके किसी परिवार जन के साथ कोई ऐसी घटना घटित हो।

किसी महिला के साथ जघन्यता होगी तो वह पहले, उस राक्षस से यह कहेगी कि जरूरा करना, पहले मैं वीडियो रिकार्डिंग ओन कर देती हूँ!!!

जैसा हमारा समाज है, एक महिला के लिए इस प्रकार की घटना को सार्वजनिक करना, लगभग असंभव है। उसके परिवार और उस महिला को भविष्य में हो सकने वाली हजार बातें सोचनी पड़ती है। सरकारी सिस्टम भरोसे लाइक हो, परिवार और नागरिक संगठनों का साथ मिले और महिला में अदम्य साहस हो तभी वह खुल कर ऐसी घटनाओं की प्रकाश में लाएगी। क्या आप इसे नहीं मानते??

मीडिया वालों ने यह बयान तो छाप व बोल दिया कि नाबालिग महिला के किसी चाचा-ताऊ का कहना है कि वह बालिग है किन्तु उसके पिता ने तो स्वयं दर्ज कराई है, उस से पूछने की जहमत तक नहीं उठाते? घटना के वक्त की स्थिति देखनी है या वर्तमान उग्र देखनी है?

अगर 28 मई को पुलिस पहलवानों व समर्थक जनता को संसद भवन तक मार्च की अनुमति नहीं देना चाहती थी तो बात समझ में आ सकती है किन्तु उनके धरना स्थल को क्यों तहस-नहस किया? उनके साथ अमानवीय व्यवहार क्यों किया गया? लगता है चाकरों में मालिक को वफादारी दिखाने के लिए किसी हद तक जाने की होड़ मची है??

एक वार्ता में एक महिला पुलिस अधिकारी ने जनता के बीच, यह कहा कि 28 मई को लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है, डिटेन किया है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। तो फिर इनके विरुद्ध संगीन जुर्म वाली धाराओं में मुकदमा क्यों दर्ज और अगर जुर्म इतना ही संगीन तो फिर छोड़ा क्यों??

मंत्री कह रहे हैं, पहलवान जांच कार्यवाही में विश्वास रखें, नेक सलाह किन्तु जांच बिना समय सीमा के मंथर गति से, क्यों?? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्ज करने के कितने दिन बाद पुलिस ने बयान दर्ज किए, कितने दिन बाद धारा 164 के बयान दर्ज हुए, कितने दिन बाद गठित हुई--क्या यह विश्वास बढाते हैं??

क्या सामान्यतः पोक्सो एक्ट में दर्ज मामलों में पुलिस ऐसे ही कार्यवाही करती है--क्या जिस व्यक्ति के विरुद्ध नाबालिग से यौन शोषण सम्बन्धी गम्भीर आरोप हों, उनके साथ पुलिस इसी तरह पेश आती है? उसे धूम-धूम कर प्रेस के माध्यम से अपनी पैरवी करने की छूट देती है, अन्य लोगों से भावनात्मक आधार पर समर्थन मांगने या प्रभावित करने की छूट देती है? मंत्री जी से अंतिम प्रश्न--जैसे अन्य पोक्सो आरोपियों से साक्ष्य एक्टर करने के लिए जांच होती है, वैसी इस मामले में क्यों अन्व?

और अब सुने एक ठेठ ग्रामीण की टिप्पणी--क्यों जी, राहुल गांधी ने 4 साल पहले किसी सभा में एक टिप्पणी कर दी, उस पर तो उसकी सदस्यता खत्म, बंगला भी छीन गया, यह कौन ऐसा महाबली है कि सारी सत्तासीन जमात चुप है? एक थोड़े पढ़े-लिखे ने समझाने की कोशिश की कि दोनों अलग-अलग मामले हैं। बात उसके गले नहीं उतरी, वह बोला-- मैं तो केवल यह कह रहा हूँ सरकारी सुनती है, मन भाती बाता। राहुल के केस का पीछा नहीं किया जाता तो वह भी रहता किन्तु उसका मामला मन भाता नहीं था। इस बाहुबली के मामले में न बोलना मन भाती बात है। है न यह फर्क?

-अतिथि सम्पादक, महावीर सिंह, आई.ए.एस. (से.नि.)



राशिफल

शनिवार 3 जून, 2023

ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत् 2080, विशाखा नक्षत्र प्रातः 6:16 तक, शिव योग दिन 2:47 तक, वणिज करण दिन 11:17 तक, चन्द्रमा वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृष, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-कर्क, बुध-मेष, गुरु-मेष, शुक-कर्क, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज रविवार प्रातः 6:16 तक है। भद्रा दिन 11:1 से रात्रि 10:14 तक रहेगी। आज चान्द पूर्णिमा व्रत, मन्वादि, चंपक चतुर्दशी (बंगाल में) है।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 7:19 से 9:01 तक, कर 12:25 से 2:07 तक, लाभ-अमृत 2:07 से 5:31 तक।

राहुकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 5:37, सूर्यास्त 7:12

मेष

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। अष्टम भाव में चन्द्रमा शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बन्तें कार्य विंगड सकते हैं। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

तुला

आर्थिक कारणों से अटक हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगे। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेंगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

वृष

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक

घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में विवाहित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

मिथुन

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रति होणी। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु

घर-परिवार के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अगर्ल कार्यों में समय खराब हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कर्क

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक मामलों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक मामलों में सोच-विचार करना ठीक रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक मामलों में सोच-विचार करना ठीक रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह

घर-परिवार के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। धार्मिक स्थिति ठीक रहेगी। कार्यक्रम बना सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बने लगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त करेगा। महत्वपूर्ण मामलों में मित्रों/सहोदरों से सहयोग मिल सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

मीन

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटक हुए कार्य बने लगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कितना ही पर्यावरण बेवजह नष्ट होता है



डॉ. रामावतार शर्मा

वे सरकार में पदस्थापित एक उच्च अधिकारी हैं। स्वाभाविक है कि उन्हें साधन एवम् धन की कमी नहीं है, तो महलनुमा आलीशान मकान का निर्माण करवा लिया। घर के सामने दो-तीन विशाल और शानदार पेड़ थे। हरे भरे लहलहाते परंतु भव्य भवन के प्रदर्शन को रोक रहे थे तो एक दिन अरी के शिकार को गए। अब साहब के घर अपने वाले वाहन पड़ोसियों के पेड़ों के नीचे गर्मी से राहत पाते हैं। इस तरह के हालात हर शहर की तकरीबन हर कॉलोनी में घटित होते नजर आते हैं। मकान का सौंदर्य प्रदर्शित करना है इसलिए पेड़ का बलिदान किया जाएगा और उसके स्थान पर सुंदर से गमले में फूलदार पौधा स्थापित कर विश्व

में बिगड़ते पर्यावरण पर चिंता की जाएगी। दूसरी तरफ जंगल में हाथी एक बायो इंजीनियर हैं जो विशाल पेड़ों के फूल, फल, पत्तियों और बीज खाता है और अपने गोबर डगर उस पेड़ के बीजों को चारों तरफ फैला कर नए जंगल की रचना करता रहता है। पर हमें हाथी दांत की चूड़ियां, मूर्तियां तथा अर्हकार तुष्टि के कुछ अन्य नमूने चाहिए तो हम दूर से राइफल द्वारा गोली चलाते हैं, फिर अपनी बहादुरी की फोटो खिंचवाते हैं मानो हाथी को मल्लयुद्ध में पछाड़ मारा हो। इतने शानदार और विशालकाय जीव की हत्या सिर्फ उसके दो दांतों के लिए करते समय मनुष्य हृदय में कम्पन तक नहीं होता है। प्रकृति अपने एक क्रियाशील इंजीनियर को सदा के लिए छो देती है। धरती पर चींटों से लेकर हाथी तक सभी जीव किसी न किसी रूप में किसी विशिष्ट नव निर्माण से जुड़े हुए होते हैं परंतु मनुष्य है जो हर समय प्रकृति को नष्ट करने में जुटा है।

दुनिया में हर साल कोई तीन करोड़ पेड़ मनुष्य अपनी जरूरतों के लिए काटता है, जिनमें से अधिकतर कटाई अनावश्यक होती है, अर्हकार तुष्टिकरण की पूर्ति करने के लिए होती है। हम लोग हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते

की परंपरा तो निभाते हैं परंतु व्यवहार में पर्यावरण को धनी बनाने का कोई कार्य नहीं करते हैं। हम लगातार इस बात को भूल जाते हैं कि प्राकृतिक संसाधन अनंत नहीं होते हैं। इन संसाधनों को हाथी जैसे बायो इंजीनियर बनकर पुनः निर्मित करते रहना पड़ता है। भारत के मध्य में अमरकंटक क्षेत्र के जंगलों की मूहता पूर्ण कटाई से हम तथाकथित नदी प्रेमी लोगों ने नर्मदा जैसी पानी से भरी बारहमासी नदी को नाले में तब्दील कर डाला है। मां गंगा, मां नर्मदा कहने मात्र से नदियां पवित्र और सुरक्षित नहीं हो जाती हैं। हम उनका उद्गम और रास्ते को बचना होता है, साफ-सुधरा तथा हरा-भरा रखना होता है परंतु इस दोनों ही मापदंडों पर हम असफल और संवेदनहीन रहे हैं। इस मामले में हमारा समाज मातृहता ही कहलाएगा।

बोते बीस सालों में भारत के शहरों तथा कस्बों में बाहनों की तीव्र वृद्धि हुई है। दिन के समय ये सब वाहन खुले में घूसे से तपते रहते हैं।

ज्यों ही रात होती है तो इन वाहनों की ह्टील चरों से ऊर्जा वातावरण में वापस छोड़ी जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार यह ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि रात का तापमान दो तीन डिग्री तक बढ़ सकता

है और शायद एक कारण है जिसकी वजह से शहरों की रातें अब ठंडी नहीं होती हैं। इस समस्या से बचने के लिए हमें जो इतने पेड़ तो लगाने चाहिए ताकि हर छोटा बड़ा वाहन छाया में खड़ा हो सके। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हिमालय घाटी का नदी तंत्र करीब 20 लाख 75 हजार वर्ग किलोमीटर भूमि को जल प्रदान करता है। इस जल से 5 लाख 77 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिंचाई होती है और विश्व में सर्वाधिक 26,432 मेगावाट जल विद्युत पैदा की जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र में तो पानी मुख्यतया बारिश से आता है परंतु अन्य सभी नदियों में पानी का स्रोत हिमालय के विशाल ग्लेशियर्स हैं जो लगातार बढ़ती वैश्विक गर्मी की वजह से पिघलते जा रहे हैं।

वैज्ञानिकों द्वारा भय व्यक्त किया जा रहा है कि ग्लेशियर्स का यह स्रोत समाप्त हो सकता है और बारिश की कमी से गंगा और ब्रह्मपुत्र भी तत्कालीन में आ सकती है। यदा कदा की अतिवृष्टि से नदियां उफान खा सकती हैं जिसके कारण बड़ी तबाही भी हो सकती है। यहां सरकार के साथ हर व्यक्ति का अपने स्तर पर प्रयास करने होगा। हम हमारा जीवन सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि सरकार

मात्र एक मानव निर्मित तंत्र है जिसमें आत्म नहीं होती। सरकार का निर्माण चाहे किन्हीं उद्देश्यों के लिए हुआ हो परंतु व्यवहार में यह प्रभावशाली लोगों के स्वार्थी की पूर्ति का साधन होती है। यदि किसी व्यक्ति को अपना और अपनी आने वाली पीढ़ियों के जीवन को सुरक्षित रखना है तो धरती के पर्यावरण पर अपने स्तर पर भी कुछ प्रयत्न करने होंगे।

पृथ्वी पर यदि हम मांसाहारी जीवों को समाप्त करते हैं तो इतने शाकाहारी जीव पनप जायेंगे कि सारे जंगल को समाप्त कर देंगे। यदि बिलों में रहने वाले जीवों को हम मार डालेंगे तो रेगिस्तान में जो थोड़े बहुत घास के पौधे पनपते हैं उनके बीज समाप्त हो जायेंगे। पहाड़ों के बिलों में रहने वाले जीवों को समूल नष्ट करने के मानवीय प्रयास भविष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। पूरी प्रकृति का निर्माण एक क्रम के तरह होता है। इस क्रम को तोड़ना मानव जाति की मूहता है जो जीव, पेड़ और पौधा जिस कार्य के लिए निर्मित हुआ है उसके कार्य को यदि बाधित किया जाता है तो यह बेवजह पर्यावरण विनाश के सिवा कुछ नहीं है।

-डॉ. रामावतार शर्मा, (चिकित्सक एवं लेखक)

मांगों को लेकर किसानों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव

चूरू, (कास)। फसल बीमा क्लेम सहित 22 सूत्री मांगों को लेकर शूकराव को किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट के सभी गेटों पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा।

किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करते हुये कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर नारेबाजी की। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प हो गई। सुबह से ही जिलेभर से किसान पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचने लगे थे। किसान सभा के महामंत्री एडवोकेट निर्मल कुमार ने बताया कि बकाया फसल बीमा क्लेम, क्रांप कटिंग के आधार पर बीमा, किसानों को 6 घंटे बिजली, मनरेगा में छह सौ रूपये का

किसानों ने मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करते हुये कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर नारेबाजी की। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प हो गई। सुबह से ही जिलेभर से किसान पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचने लगे थे। किसान सभा के महामंत्री एडवोकेट निर्मल कुमार ने बताया कि बकाया फसल बीमा क्लेम, क्रांप कटिंग के आधार पर बीमा, किसानों को 6 घंटे बिजली, मनरेगा में छह सौ रूपये का

भुगतान सहित 22 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है, उनकी लंबे समय से चली आ रही बाजिब मांगों को नहीं माना जा रहा है। एडवोकेट निर्मल कुमार ने बताया कि अब भी अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानेगी तो मजबूरन चक्का जाम करना पड़ेगा।



फसल बीमा क्लेम सहित 22 सूत्री मांगों को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन किया।

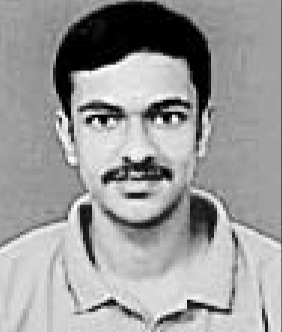
स्नेक कैचर गजेंद्र सिंह को सांप ने काटा, जोधपुर रैफर

पाली, (निर्स)। पाली शहर में अब तक सैकड़ों जहरीले कोबरा सहित अन्य सांपों को पकड़कर आवासीय क्षेत्र से जंगल में छोड़ने वाले स्नेक कैचर गजेंद्र सिंह मंडली को गुरुवार देर शाम को सांप के रेस्क्यू के दौरान सांप ने काट लिया। जिन्हें इलाज के लिए बांगड हॉस्पिटल लाया गया। जहां से देर रात को उन्हें जोधपुर रेफर किया गया। हालात खतरे से बाहर बताई है।

घटना गुरुवार देर शाम को पाली के हाऊसिंग बोर्ड के पास एक फॉर्म हाऊस पर हुई। फॉर्म हाऊस पर सांप आने की खबर पर स्नेक कैचर गजेंद्रसिंह मंडली सांप को पकड़ने पहुंचे। इस दौरान अचानक सांप ने उन्हें काट लिया। जिन्हें तुरंत उपचार के लिए पाली के बांगड हॉस्पिटल लाया गया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गुरुवार देर रात को उन्हें जोधपुर रेफर किया गया। उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है।

पाली में बड़ी संख्या में जहरीले कोबरा सांप हैं। जिनके काटने पर बचने की उम्मीद कम रहती है। पाली में पहले भी दो स्नेक कैचर की दौरान सांप ने मौत हो चुकी है। ऐसे में स्नेक कैचरों को चाहिए कि सांप को पकड़ते समय पूर्ण सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें।

राजकीय ऋणग्रस्तता और इसके स्वाभाविक मायने



वैभव शर्मा

ऋण यह शब्द सदैव से ही प्रगति या समस्याओं के बीच में उलझता हुआ या नजर आया है। बड़े लोग अक्सर किसी भी प्रकार के ऋणों से दूर रहने या बचने की सलाह देते हुए प्रतीत होते हैं, वहीं आधुनिक सोच के अर्थशास्त्री इसे विकास का एक आवश्यक अंग मानते हैं। चर्चा से उत्पन्न होते हुए कुछ सवाल यों हैं कि क्या राजकीय स्तर पर ऋण लिया जाए या नहीं, कितना लिया जाए, किन उद्देश्यों के लिए लिया जाए, किन परिस्थितियों में

लिया जाए, क्या ऋण लेने के स्थान पर कोई वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध हैं, क्या खर्च काम करके ऋणों को समायोजित किया जा सकता है या क्या आय के स्रोत बढ़ाकर ऋण लेने की परेशानियों से बचा जा सकता है?

यद्यपि परिवार अपने खर्चों को भली भाँति अपनी आय के स्रोतों से समायोजित कर पाने में किसी हद तक कामयाब रहते हैं, परन्तु आज्ञादी के वाद निरंतर सरकार ऐसा करने में सक्षम नहीं रही है। पारिवारिक स्तर पर आय और व्यय के दीर्घकालीन आंकलन को नियोजित करने और वापिस ऋण चुकाने की क्षमता का आंकलन करके संपत्ति बनाने, बच्चों की शिक्षा, अनिश्चितताओं का मुकाबला करने के लिए ऋण लिए जाते हैं, परन्तु यह एक कठिन निर्णय तब हो जाता है जब आप किसी कंपनी के सर्वोच्च पदों पर हो और कंपनी के शेयर होल्डर्स की तरफ से ऋण लेने का फैसला करते हो। यह निर्णय और भी कठिन तब हो जाता है ऋण उधारता के बोझ से राज्य और राज्य की जनता के सीधे जुड़े होने का मसला हो। ऐसे में ऋण लेने के इन कठिन निर्णयों का

आर्थिक, सामाजिक और नैतिक स्तर पर मूल्यांकन अति आवश्यक हो जाता है, और आर्थिक स्तर पर बेहतर से बेहतरतीन व्यवस्था बनाने के लिए यह और भी जरूरी है कि राज्य के लिए ऋण लेने के फैसलों का मूल्यांकन एक आम आदमी की परिधि में हो।

ऋण क्यों लिया जाए इसका निर्णय सदन में बैठे हुए कार्यपालिकाओं को करना होता है। यथासंभव कार्यपालिकाओं को अपने इन निर्णयों में संवाद द्वारा आम जनता को भागीदार बनाना चाहिए। लेकिन ऋण कितना लिया जाए यह निर्णय एक कठिन निर्णय है। आज के दायरे में कुछ राज्यों की सरकारों पर यह आक्षेप आता रहा है कि वे ऋण प्रस्तुता का मुकाबला करने में बहुत हद तक कामयाब नहीं रही हैं। ऋण कितना लिया जाए इस प्रश्न के कई पैमाने हो सकते हैं जिनमें ऋण के आवश्यकता, ऋण के तीव्रता और ऋण को वापिस चुका पाने की क्षमता, आदि हैं। ऋण को वापिस चुका पाने की क्षमता का जहा तक सवाल है जोडीपी ऋण-अनुपात एक ऐसा सूचकांक माना गया है जो इस संदर्भ में

कुछ प्रकाश डालता है। सामान्य शब्दों में यदि एक व्यक्ति की आय 1 लाख रुपये है और उस पर ऋण का बोझ 20,000 रुपये है जो की 20 प्रतिशत है, वही एक व्यक्ति जिसकी आय 1 करोड़ रुपये है उसके द्वारा लिया गया 10 लाख रुपये का बड़ा लोन भी ज्यादा इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि यह ऋण उसकी आय का 10 प्रतिशत ही है जो की ऋण वापिस चुका पाने की सहजता को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार अलग-अलग जोडीपी वाले राज्यों और अलग-अलग जोडीपी वाले देशों में भी ऋण लेने की क्षमता का पैमाना भी अलग-अलग होना चाहिए।

यदि हम भारत के विभिन्न राज्यों में जोडीपी ऋण अनुपात के सन्दर्भ का अवलोकन करें तो 2021-22 कारिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन ये बताया है की पंजाब राज्य में ये अनुपात काफी अधिक जो की 53.3 प्रतिशत है, राजस्थान में 39.5 प्रतिशत है, वही महाराष्ट्र में महज 17.9 प्रतिशत, ओडिशा में 18 प्रतिशत तथा तमिलनाडु में 27.4 प्रतिशत है।

किसी संस्था या संस्थाओं द्वारा लिए गए बेहतरतीन निर्णय बिना राजनीति के

संघीय देशों में राज्यों और संघ द्वारा किस प्रकार सहजता से स्वीकार कर लिए जाते हैं इसका एक नायाब उदाहरण कार्यपालिकाओं में व्यवस्थापिका के कुल सदस्यों का 15 प्रतिशत की सीमा बाँध देना है।

इसी प्रकार यदि सांख्यिक स्तर पर जोडीपी ऋण-अनुपात का सर्व सहर्मात से निर्धारण कर लिया जाए तो न सिर्फ राजनैतिक प्री की रेवडिजि बांटने और अकुशल तरीकों से अर्थव्यवस्थाओं के संचालन पर आरोप प्रत्यारोपों पर रोक लग सकेगी बल्कि राज्यों और केंद्र के सामने भावी योजनाओं के निर्धारण में ऋणों की भूमिका और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। भारत जैसे संघीय देशों में नीतियों के निर्धारण की खूबसूरती इसी में है की विभिन्न संस्थाओं द्वारा मिल जुलकर समझदारी पूर्वक विभिन्न जटिल वित्तीय मुद्दों पर समावेशी गाइडलाइन्स तैयार कर ली जाए जो कि भावी नीतियों के निर्धारण में पथ प्रदर्शक साबित हो सकेंगी।

-वैभव शर्मा, स्टूडेंट, मद्रास स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स